कार्यशाला | इंक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन, सुदेश बोले

लोगों की भागीदारी से ही सशक्त लोकतंत्र

- खामियां गिनाने के बजाय सुझाव भी दें
- मीडिया-सरकार बने साझीदार और भागीदार

सन्मार्ग @ वरीय संवाददाता

मीडिया फॉर इंक्लूसिव चेंज कार्यशाला में बोलते उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो। छाया : इकबाल

रांची : योजनाओं के विकेंद्रीकरण और ग्राम सशक्तीकरण में मीडिया सबसे बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकता है। विकास योजनाओं की राशि गांवों तक पहुंचे, इसका प्रयास किया जा रहा है। मीडिया और सरकार को साझीदार और भागीदार बनकर काम करना होगा। उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने सोमवार को इंक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन में यह बात कही। योजना आयोग के सहयोग से यह कार्यक्रम होटल बीएनआर चाणक्य में हो रहा है। सुदेश बोले, लोकतंत्र को सशक्त बनाना है तो निर्णय में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। पंचायत चुनाव से यह अवसर मिला है, लेकिन केंद्र से कई योजनाएं थोपी जाती हैं जबकि इसका चुनाव भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आम लोगों की मूल जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो अबतक तय नहीं है। इसलिए राज्य सरकार और ग्राम सभाओं को योजनाओं के चयन का जिम्मा सौंपा जाये। राज्य में बीपीएल परिवार अभी तक पूरी तरह चिह्नित नहीं हो पाये हैं। ग्राम सभाओं को भी यह ताकत नहीं है कि वह उन सबल लोगों के खिलाफ बोले जो बीपीएल की सूची में शामिल हो गये हैं। इसलिए जरूरी है कि मीडिया और सरकार सूचनाओं का आदान-प्रदान करे। मीडिया सिर्फ खामियां नहीं गिनाये, सुझाव भी दे। सरकार पर लोगों की निर्भरता कम हो, इसके लिए गांवों में ही रिर्सोस डेवलप किया जाये। कार्यशाला में योजना एवं विकास सचिव अविनाश कुमार, गवर्नेंस सलाहकार (यूएनडीपी) टीआर रघुनंदन, वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश, जिला योजना विशेषज्ञ (सीडीडीपी) सुंदर एन मिश्रा, आइएम फॉर चेंज के निदेशक विपुल मुद्गल, सत्येंद्र रंजन, अर्थशास्त्री प्रोफेसर रमेश शरण और मंथन के सुधीर पाल ने भी विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में मीडिया और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग शामिल हुए।

राज्य सरकारें सिर्फ एजेंट बनीं

प्लानिंग कमीशन में संयुक्त सचिव रहे टीआर रघुनंदन ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ बजटरी प्लानिंग करती है और पैसा राज्यों को भेज देती है। इसे प्लानिंग नहीं कहा जा सकता। केंद्र में प्लान बनता है और राज्य सरकारें उसे सिर्फ लागू करती हैं। इसका विकेंद्रीकरण करने से केंद्र पैसा रोकने की बात करती है।

राज्य सरकारें केंद्र की एजेंट बन कर रह गयी हैं। दरअसल विकेंद्रीकरण नहीं एजेंसीकरण हुआ है। अधिकारी विकेंद्रीकरण नहीं चाहते हैं। केरल में 33 प्रतिशत राजस्व पंचायत में जाता है। बंगलुरु में 3.50 लाख घर बिना प्लानिंग के बने हुए हैं। इसे रेगुलर करने का सरकार पर प्रेशर है। अविनाश कुमार ने कहा कि मीडिया पहरेदार बनकर योजनाओं की मॉनिटरिंग करे। जबतक ऐसा नहीं होगा तबतक प्रजातंत्र की अवधारणा पूरी नहीं होगी। सुंदर एन मिश्रा ने कहा कि विकेंद्रीकरण प्लानिंग मॉनिटरिंग मीडिया करे, क्योंकि उनका रोल काफी बढ़ गया है। पत्रकार हरिवंश ने कहा कि दुनिया में रिसोर्स खत्म हो रहा है। छोटे स्तर पर प्लानिंग हो ताकि रिर्सोस बचा रहे। विपुल मुद्गल ने कहा कि मीडिया की जवाबदेही बढ़ रही है। मीडिया को आगे बढ़ना है जो उसे भागीदार बनना होगा। रमेश शरण ने कहा कि गांवों को हक नहीं दिया जा रहा है। प्लानिंग का प्रयास सही नहीं है। विकेंद्रीकरण की लड़ाई आसान नहीं है। सुधीर पाल ने कहा कि विकेंद्रीकरण के मामले में झारखंड सबसे नीचले पायदान पर है।